

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं० : स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या-196/2017-18/

दिनांक : /05/2018

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम - रुद्रपुर

जनपद- ऊधम सहं नगर

वषय : नगर निगम रुद्रपुर, का वर्ष 04/2016 से 03/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 10 प्रस्तर एवं STAN 03 प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या सचव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी स्थानीय निकाय

दिनांक : /05/2018

सं०: स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या-196

प्रतिप निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड निकट साईं इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट), द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोड: 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या AIR-196/213 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर, जनपद-उधम सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सतेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री हिमांशु शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री राजवेश भट्ट, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02/03/2018 से 15/03/2018 तक श्री एस के वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एल.एस. लंगवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोहर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 11/12/2016 से 04/01/2017 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें वर्ष 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ---

1. उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : ----
2. उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्या : --
3. भौगोलिक क्षेत्र : 805.26 हेक्टेअर
4. जनसंख्या : 140844
5. निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 20
6. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या : 01
7. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या : 02
8. कर्मचारियों की संख्या : 88
9. नगर निगम की संघर्षता:--
10. नगर निगम के अपने प्रोजेक्ट :--
11. योजनाओं की संख्या :
12. (अ) सामाजिक संरक्षा :
(ब) रोजगार सृजन से संबंधित :
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनाएँ :
(द) लाभार्थियों की संख्या :
13. वर्ष के दौरान कर, रेंट्स इयूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :
14. वर्ष के दौरान कुल व्यय
(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं
संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

15. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचन निकाय द्वारा चर्चा की गयी
तथा उसे पारित किया गया :

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को
सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विध: लेखापरीक्षा में नगर निगम रुद्रपुर ,
जनपद- उधम सिंह नगर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण
अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन
नगर निगम रुद्रपुर , जनपद- उधम सिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित
है। माह 03/2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया। --- (जिस योजना का चयन किया
गया उसका नाम अंकित किया जाय) का वस्तुतः विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन

.....
..... (प्रतिचयन विध का नाम अंकित किया जाय) के
आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-
महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट,
1971) की धारा 20(1) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के
अनुसार सम्पादित की गयी।

नगर निगम रुद्रपुर

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना		गैर स्थापना	
							आ धक्य (+)	बचत (-)	आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	0	168092340	49002435	49002435	116654579	208684366	0	0	76062553	0
2015-16	0	76062553	51135181	51135181	121859384	89718719	0	0	108203218	0
2016-17	0	108203218	51784828	51784828	219169037	150841330	0	0	176530924	0

नगर निगम- रुद्रपुर (धनरा श लाख रु मे)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष	1680.92	760.63	1082.02
वर्ष के दौरान प्राप्तियां			
(क) केन्द्रांश	208.22	202.9	1185.08
(ख) राज्यांश	1205.96	1253.15	1211.45
(ग) अन्य प्राप्तियां	242.39	273.89	313.01
व्यय	2576.87	1408.54	2026.26
अंतिम शेष	760.62	1082.02	1765.3

(i) वृत्तीय वर्षों 2014-17 के दौरान इकाई के वर्ष के दौरान कुल आय मे निजी स्रोतों से आय का प्रतिशत क्रमशः 15, 16 एवं 12 था, निजी स्रोत से आय मे निरंतर कमी हो रही थी ।

(ii) इकाई द्वारा कुल उपलब्ध रा श के क्रमशः 53 प्रतिशत (वर्ष 2016-17) ही व्यय कर गए ।

नगर निगम- रुद्रपुर (धनरा श लाख रु मे)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष	1680.92	760.63	1082.02
वर्ष के दौरान प्राप्तियां			
(क) केन्द्रांश	1205.96	1253.15	1185.08
(ख) राज्यांश	208.22	202.9	1211.45
(ग) अन्य प्राप्तियां	242.39	273.89	313.01
व्यय	2576.87	1408.54	2026.26
अंतिम शेष	760.62	1082.02	1765.3

(i) वृत्तीय वर्षों 2014-17 के दौरान इकाई के वर्ष के दौरान कुल आय मे निजी स्रोतों से आय का प्रतिशत क्रमशः 15, 16 एवं 12 था, निजी स्रोत से आय मे निरंतर कमी हो रही थी ।

(ii) इकाई द्वारा कुल उपलब्ध रा श के क्रमशः 53 प्रतिशत (वर्ष 2016-17) ही व्यय कर गए ।

नगर निगम- रुद्रपुर (धनरा श रु मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वत्त	0	2082200 0	2082200 0	1388200 0	6940000
2014-15	सांसद नि ध	0	0	0	0	0
2015-16	केन्द्रीय वत्त	6940000	2000000 0	2694000 0	0	26940000
2015-16	स्वच्छ भारत मशन	0	290000	290000	0	290000
2015-16	सांसद नि ध	0	0	0	0	0
2016-17	केन्द्रीय वत्त	26940000	3258500 0	5952500 0	3883840 0	20686600
2016-17	स्वच्छ भारत मशन	290000	723040	1013040	319418	693622
2016-17	अमृत योजना	0	8490000 0	8490000 0	4182435 1	43075649
2016-17	सांसद नि ध	0	299830	299830	299830	0

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1:- उत्तराखंड अधप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों का सम्पादन न कराया जाना तथा त्रुटिपूर्ण आगणन का गठन कया जाना।

उत्तराखंड अधप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 12 (2) तथा नियमावली, 2017 के नियम अनुसार रु 25.00 लाख तक के कार्यों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए, क न्यूनतम तीन निवदाएँ प्राप्त हो, प्रश्नगत सामग्री के लिए निवदा दस्तावेज़, पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची से तीन से अधिक फर्मों को सीधे स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर से भेजे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सी मत निवदा के लिए वेबसाइट द्वारा भी प्रचार कया जाना चाहिए। नियम 12 (3) के अनुसार यह सुनिश्चित कया जाना चाहिए क प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिक अनुक्रयाशील निवदा प्राप्त करने के लिए यथा संभव अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को चन्हित कया जाना चाहिए। वज्ञापन द्वारा निवदा पृछा के संबंध में नियम 13 (1) तथा नियमावली 2017 के नियम 10 में प्रावधानित है क रु 25 लाख तथा उससे अधिक क अनुमानित लागत की सामग्री की अधप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में वज्ञापन द्वारा निवदा आमंत्रित की जाय। रु 25 लाख से कम कीमत की सामग्री की अधप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में वज्ञापन के माध्यम से की जाए।

नगर निगम के निर्माण कार्य संबंधी चयनित पत्रावलयों (सूची के अनुसार) की जांच में देखा गया क वतीय वर्ष 2016-17 में संपादित निर्माण कार्यों, जिनकी लागत रु 5 लाख से 28 लाख तक थी, के आवंटन प्राप्त तीन - तीन निवदाओं के आधार पर कए गए थे। आवंटन वभागीय दरों से नीचे 0 -1.50 प्रतिशत पर कए¹ गए थे। स्पष्ट था क कार्यों के आवंटन में अधप्राप्ति नियमावली के अनुक्रम में अधिक प्रतियोगी दरें प्राप्त नहीं की गयी थी।

कार्य के आवंटन कए जाने के उपरांत निम्न मुख्य शर्तों के अधीन ठेकेदार के साथ अनुबंध पत्र गठित कया गया था:

¹ कार्य के आवंटन की स्थिति: वभागीय दर से 0.25 प्रतिशत कम पर : 34 कार्य, 0.25 - 0.50 प्रतिशत कम पर : 19 कार्य , 0.50 - 0.75 प्रतिशत कम पर : 04 कार्य , 0.75 - 1.00 प्रतिशत कम पर : 06 कार्य , 1.50 प्रतिशत से अधिक कम पर : 03 कार्य तथा आगणन दर पर : 06 कार्य

(i) ठेकेदार की निवदा राश उत्तराखंड अधप्राप्ति समिति द्वारा स्वीकृत है, कार्य को दिये गए आकार तथा प्रकार में पूरा करेगा,

(ii) ठेकेदार कार्य को समय के अंदर पूरा नहीं करता है तो उसके वरुद्ध लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा 01 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से वसूली की जाएगी,

(iii) कार्य समाप्ति के एक वर्ष तक ठेकेदार की डेफेक्ट लैबिलटी होगी,

चयनित कार्यों की पत्रावलियों में कार्यों के आवंटन, क्रयान्वयन स्तर पर निम्न त्रुटियाँ पायी गयीं।

- कार्य के आवंटन हेतु उत्तराखंड अधप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप अधक अनुक्रयाशील दरे प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं किए गए थे। कार्य का आवंटन सीमत रूप से तीन प्राप्त निवदाओं के आधार पर किया गया था,
- कार्य के गठित आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं ली गयी थी, जिसके कारण कार्य के तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी,
- कार्य के प्रारम्भ किए जाने से पूर्व कार्य स्थल के फोटोग्राफ, कार्य के क्रयान्वयन के दौरान फोटोग्राफ तथा कार्य के सम्पादन के उपरांत के फोटोग्राफ पत्रावली में उपलब्ध नहीं थे,
- कार्यों के ले - आउट स्वीकृत आगणन में संलग्न नहीं थे, जिससे उससे क्रयान्वयन संबंधी मानदंडों को सुनिश्चित किया जा सके,
- कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की जांच संबंधी प्रतिवेदन पत्रावली में संलग्न नहीं थे,
- वार्ड 17 में डॉक्टर कॉलोनी गली संख्या 02 प्रभात प्रेस वालों के आवास से दीपमाला हॉस्पिटल तक सी सी रोड निर्माण आगणन (रु 29.35 लाख) एवं वार्ड संख्या 17 में पी ए सी के आवास के सामने सी सी रोड निर्माण में “dismantling of cement concrete pavements by mechanical means using pneumatic tools” क्रमशः जिसकी मात्रा 286.5 cum एवं दर रु 1760.10 थी तथा 157.50 cum एवं दर रु

1760.10 थी के dismantling से होने वाली आय को आगणन मे समायोजित नहीं कया गया था,

- निर्माण से संबन्धित कार्य पंजी का रखरखाव नहीं कया जा रहा था, जिससे कार्य की भौतिक एवं वतीय प्रगति का अनुमान नहीं लगाया जा सका,
- वार्ड संख्या 9 ट्रेनिंग सेंटर होम साइंस कॉलोनी मे सी सी रोड निर्माण पत्रावली की जांच मे देखा गया क ठेकेदार द्वारा प्रार्थना पत्र दिये बिना ही कनिष्ठ अभयंता द्वारा वचलन क संभावना व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त को टिप्पणी प्रस्तुत की गयी थी, इससे स्पष्ट था क निर्माण मे ठेकेदार को लाभ दिये जाने के उद्देश्य से इस प्रकार की टिप्पणी की गयी थी।

स्पष्ट था क इकाई द्वारा निर्माण कार्यो के आवंटन, क्रयान्वयन मे अधप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कया गया था तथा कार्य के क्रयान्वयन मे गुणवत्ता सुनिश्चित कए जाने हेतु ठोस उपाय नहीं कए गए थे।

लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे इंगत कए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया नियमानुसार निवदा आमंत्रित की गयी थी तथा तकनीकी स्वीकृति नियुक्त तकनीकी अधिकारी द्वारा ली गयी थी। सामग्री की जांच करने के उपरांत ही भुगतान कया जाएगा। वार्ड 17 मे डॉक्टर कॉलोनी गली संख्या 02 प्रभात प्रेस वालों के आवास से दीपमाला हॉस्पिटल तक सी सी रोड निर्माण मे तोड़ी गयी सामग्री का उपयोग नहीं कया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्यों क कार्य का आवंटन प्रतियोगी दरे न लेकर वभागीय दरो से मात्र 0-1.50 प्रतिशत नीचे पर सम्पन्न कराये गए थे, कार्य के सम्पादन के उपरांत सामग्री की जांच कराया जाना संभव नहीं होगा। वार्ड 17 मे डॉक्टर कॉलोनी गली संख्या 02 प्रभात प्रेस वालों के आवास से दीपमाला हॉस्पिटल तक सी सी रोड निर्माण मे dismantling से होने वाली आय को आगणन मे समायोजित नहीं कया जाना त्रुटिपूर्ण आगणन गठन का द्योतक था।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- नगर निगम द्वारा फेरी नीति लागू कए जाने संबंधी कार्यवाही में रु 5.29 लाख का निष्फल व्यय |

उत्तराखंड शासन द्वारा सृजित उत्तराखंड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजी वका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय वनियमन) नियमावली 2014² के अनुसार :

- प्रत्येक नगर निकाय में फेरी क्षेत्रों, स्थानों अथवा बाजारों का चंहांकन तथा सीमांकन नगर फेरी स मति द्वारा कया जाएगा (4 क)
- नगर फेरी स मति द्वारा नगर में वद्यमान समस्त फेरी व्यवसायियों का डिजिटलाइज्ड फोटो सर्वेक्षण नियमावली लागू होने के एक माह के मध्य पूर्ण कर उन्हें सूचीबद्ध कया जाएगा (5 (1))
- नगर फेरी स मति की माह में न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जाएगी (13 (1))
- नगर फेरी स मति की संस्तुति पर स्थानीय निकाय कसी भी क्षेत्र अथवा इसके भाग को जनहित में नो वें डंग जोन घो षत कर सकता है तथा इन क्षेत्र के फेरी व्यवसायियों को वें डंग जोन / राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा वस्था पत कर सकता है। (20 (1))

इकाई की लेखापरीक्षा (मार्च 2018) में देखा गया क निगम को निदेशक, राज्य वकास अभकरण (सूडा) द्वारा रु 20.50 लाख की धनराश प्रेषत की गयी थी (नवम्बर 2014) , इस राश में से रु 5.00 लाख के व्यय से फेरी व्यवसायियों के सर्वेक्षण, उन्हें पहचान पत्र जारी करने, योजना तैयार करने सम्बन्धी कार्य कए जाने थे। नगर फेरी स मति का गठन कर कार्य प्रारम्भ कया गया तथा मे. युग एसो सयेट्स, लखनऊ (m/s yug associates) को फेरी व्यवसायियों के सर्वेक्षण, उन्हें पहचान पत्र जारी करने, योजना तैयार करने हेतु चयनित कया गया था (अप्रैल, 2015), लेखा परीक्षा (मार्च 2018) तक फर्म द्वारा कुल 3625 फेरी व्यवसायियों का सर्वेक्षण कया गया था तथा अन्य कार्य लंबित थे,

² शहरी वकास अनुभाग -2 की अधसूचना संख्या 1614 /V (2) श व -2014 /246 (सा) 04 - टी सी 1 देहारादून : दिनांक 17 अक्टूबर , 2014

इसके लिए फर्म को रु 5.29 लाख का भुगतान किया जा चुका था (जुलाई 2015)। फेरी व्यवसायियों के सर्वेक्षण से पूर्व अपेक्षित वेंडिंग जोन निर्धारित किए जाने हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गयी थी और बिना भूमि के निर्धारण के ही दो वर्ष पूर्व सर्वेक्षण पर किया गया व्यय रु 5.29 लाख निष्फल था।

लेखा परीक्षा में इंगत किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना (ओक्टूबर 2014) में यह नहीं बताया गया था कि फेरी नीति के क्रयान्वयन से पूर्व भूमि का चयन किया जाना था, जानकारी के अभाव में यथा समय पर भूमि का चयन नहीं किया जा सका। निगम द्वारा भूमि के चयन का कार्य किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भूमि के चयन के बिना वेंडिंग जोन की स्थापना संबंधी कार्य को किया जाना संभव नहीं है तथा बिना भूमि के चयन के सर्वेक्षण संबंधी कार्य औचित्यहीन था, जिस पर किया गया व्यय रु 5.29 लाख निष्फल था।

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3:- वतीय वर्ष 2016-17 मे कर / कराया / तहबाजारी आदि की वसूली का कम रहना।

नगर निगम, रुद्रपुर के कर वभाग से संबन्धित मांग एवं वसूली से संबन्धित दस्तावेजो / पत्रवा लयों की जांच मे देखा गया क व भन्न करों / शुल्कों के ववरणो के अनुसार बकाया एवं वसूली का ववरण निम्न था:

(रा श रु लाख मे)

क्र.सं.	मद का नाम	31.03.2017 तक का अवशेष	वर्तमान मांग (वतीय वर्ष 2017-18)	कुल योग	कुल वसूली (प्रतिशत)
1.	गृहकर	25.00	95.00	120.00	42.89
2.	शो टैक्स	1.12	0.00	1.12	0.00
3.	कराया	11.88	16.25	28.13	25.94
4.	लीजमनी	0.32	0.50	0.82	0.00
5.	वज्ञापन	0.00	34.30	34.30	5.00
6.	तहबाजारी	0.00	27.28	27.28	24.32
7.	पा र्कग शुल्क	0.00	44.28	44.28	41.65
8.	स्लाटर हाउस	0.00	8.33	8.33	3.54
9.	लाइसेन्स ठेला/ रिक्शा	0.00	15.11	15.11	14.33
10.	अन्य	0.00	45.00	45.00	41.41
	योग:	38.32	286.05	324.37	199.08 (61)

उक्त से स्पष्ट था, क निगम के कुल बकाए के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत 61 था, जो निगम के प्रभावी राजस्व संकलन का द्योतक नहीं था।

लेखा परीक्षा (मार्च 2018) मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क कर्मचारियो की कमी के कारण वसूली का प्रतिशत कम है।

इस संबंध मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यो क कर वभाग के मुख्य पदो पर स्वीकृति के सापेक्ष का र्मक तैनात³ थे।

निगम द्वारा स्वयं के राजस्व की वृद्ध हेतु प्रभावी प्रयास न कए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

³ कर अधीक्षक: स्वीकृत 02 तैनात 01, कर निरीक्षक : स्वीकृत 04 तैनात 03

भाग 2(ब)

प्रस्तर 4:- इकाई द्वारा जल संयोजन के बिलों का भुगतान/निस्तारण न करने के कारण इकाई क देनदारी मे रु 904788/- क वृद्ध होना ।

कसी भी इकाई को देनदारियों का समय पर भुगतान कया जाना आवश्यक है जिससे देनदारियों उत्तरोत्तर वृद्ध से बचा जा सकें।

इकाई के जल संयोजन बिलों से संबन्धित पत्रवा लयों की जांच मे पाया गया क उत्तराखंड जल संस्थान, रुद्रपुर के द्वारा नगर निगम रुद्रपुर को माह 01/2018 से 03/2018 तक की अव ध हेतु निम्न ल खत बिल प्रेषत कए गए थे :-

क.सं.	जल संयोजन स्थल	बिल डमांड संख्या	बिल ति थ	बिल धनरा श
01	नगर पा लका रुद्रपुर	2435/272	05.03.2018	2031.00
02	अ धशासी अ धकारी आवास	2487/295	05.03.2018	2031.00
03	कार्यालय परिसर	53	05.03.2018	9700.00
04	नगर पा लका सब्जी मंडी	52	05.03.2018	873138.00
05	संजय मल्क बार, रुद्रपुर	51	05.03.2018	31650.00
योग				918550.00

इन बिलों मे से प्रथम तीन बिलों का भुगतान इकाई द्वारा निय मत रूप से कया जा रहा है परंतु क्रम संख्या 04 एवं 05 पर उल्ले खत बिलों का भुगतान इकाई द्वारा नहीं कया जा रहा है। जिससे इन बिलों के प्रति देनदारी बढ़ती जा रही है तथा साथ ही वलंब शुल्क की रा श भी उत्तरोत्तर बदती जा रही है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली मे संलग्न दिनांक 30/03/2015 की टिप्पणी मे क्रमांक 2(अ धशासी अ धकारी आवास) मे कार्यालय स्था पत हो जाने के कारण जल संयोजन वच्छेद करने तथा क्रमांक 1 व 3 कार्यालय से संबन्धित होने के कारण दोनों मे से एक जल संयोजन रखना प्रस्ता वत था जिससे उच्च धकारी भी सहमत थे तथा क्रम संख्या 4 हेतु जांच कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया था । परंतु पत्रवा लयों मे जल संयोजन वच्छेदन एवं क्रम संख्या 04 के संबंध मे आगे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी । इस प्रकार न तो क्रम संख्या 01 से 03 के स्थान पर कार्यालय के लए एकल जल संयोजन कया गया न ही क्रम संख्या 04 व 05 के बिलों का भुगतान कया गया । क्रम संख्या 04 व 05 के बिलों को निस्तारित करने हेतु कए गए कसी प्रयास की जानकारी भी पत्रावली मे नहीं थी । इस प्रकार जहां एक और क्रम संख्या 01 से 03 को एकल जल संयोजन मे न बदलने से इकाई को अतिरिक्त भुगतान करना पढ रहा था वहीं क्रम संख्या 04 व 05 के बिलों का भुगतान अथवा निस्तारण के लए कोई कार्यवाही इकाई द्वारा नहीं की गयी जिससे इकाई पर देनदारी अनवरत बढ़ती जा रही थी जो वलम्ब शुल्क सहित रु 904788/- हो चुकी है ।

इस और इंगत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क दायित्वों क निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाएगी

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 5:- निर्माण कार्यों के गठित आगणनों पर सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति न लया जाना ।

प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 562/xxvii (7)/ 2010 दिनांक: 24 मई 2010 द्वारा “वर्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन- (2010)” को निर्गत किया गया था, इसके अंतर्गत ठेके एवं टेंडर के संबंध में निम्न रूप में प्रावधान कए गए थे।

अधिकार का प्रकार	कसके द्वारा प्रयोग कया जाएगा	परिसीमाए	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
छोटे निर्माण कार्यों के निष्पादन तथा सभी प्रकार के मरम्मतों के लए टेंडर/ ठेके स्वीकृत करना	प्रशासकीय वभाग	पूर्ण अधिकार	वर्तीय संग्रह खंड - 5 भाग	
	वभागाध्यक्ष	आय व्ययक प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु 5 लाख तक	-1 के पैरा 264 बजट उपलब्धता एवं उत्तराखंड अधप्राप्ति	आय व्ययक प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु 50 हजार तक
	कार्यालयाध्यक्ष	आय व्ययक प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु 1.00 लाख तक कन्तु शर्त यह है क अनुमान वभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर दिये गए हो	नियमावली - 2008 के अधीन	आय व्ययक प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रु 25 हजार तक कन्तु शर्त यह है क अनुमान वभागाध्यक्षो द्वारा स्वीकृत कर दिये गए हो।

नगर निगम द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 मे संपादित निर्माण कार्यो⁴ की चयनित पत्राव लयो की जांच मे देखा गया क निर्माण कार्यो के गठित आगणनो पर तकनीकी स्वीकृति सहायक अभयंता, नगर निगम द्वारा प्रदत्त थी। स्पष्ट था क कार्यो के आगणन की सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा स्वीकृति लए बिना ही कार्य संपादित कराये गए थे तथा दी गयी स्वीकृति बिना ति थ के थी।

लेखापरीक्षा मे इंगत कए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है, अभयंत्रण वभाग मे योजना स्वीकृति अधशासी सहायक अभयंता जो नियुक्त कए गए हो, के द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी जाती है, कार्य स्वीकृति के अधिकार बोर्ड मे निहित है। उत्तर मान्य नहीं है क्यो क निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति देने संबंधी वत्तीय सीमा का कोई निर्धारण इकाई स्तर पर नहीं कया गया था, सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति न दिये जाने से स्थायी परिसंपत्त के निर्माण की गुणवत्ता के अधोमानक होने की संभावना से इंकार नहीं कया जा सकता।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

⁴ (i) कार्य लागत 0-5 लाख तक: शून्य, (ii) 5-10 लाख : 24 कार्य, (iii) 10-15 लाख : 05 कार्य , (iv) 15-20 लाख : 05 कार्य तथा (v) 20 लाख से अधिक के कार्य : 16, कुल कार्य 50।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 6:- रु 73.78 लाख की लागत से संपादित सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों के त्रुटिपूर्ण आगणन पर कार्य का क्रयान्वयन कराया जाना ।

नगर निगम द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 मे संपादित निर्माण कार्यों के चयनित पत्राव लयों की जांच मे देखा गया क इकाई द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण के निम्न कार्य कराये गए थे।

(रु लाख मे)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य की लागत
1.	वार्ड संख्या 9 सोनिया होटल के सामने सामुदायिक भवन का निर्माण	22.20
2.	वार्ड संख्या 1 मे मुखर्जी नगर मे जन मलन केंद्र का निर्माण	28.44
3.	वार्ड संख्या 8 संत कबीर पार्क मे जन मलन केंद्र का निर्माण	23.14
	कुल लागत	73.78

गठित आगणन के अनुसार निर्माण कार्यों मे मुख्यतः निम्न कार्य प्रस्ता वत थे:

कार्य की मर्दें	कार्य के नाम			
	संत कबीर नगर पार्क मे जन मलन केंद्र	मुखर्जी नगर मे जन मलन केंद्र	सोनिया होटल के सामने सामुदायिक भवन	
Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete 1:1.5:3	Qty in cum @ Rs 6648.25 per	40.46	28.83	27.35
	Amount (Rs in lakh)	2.69	1.92	1.82
Reinforced cement concrete work in walls	Qty in cum @ Rs 7548.99 per	72.10	60.99	31.31
	Amount (Rs in lakh)	5.44	4.60	2.36

Reinforced for RCC work including cutting, bending, placing in position and binding all complete	Qty in quintal @ Rs 7266.95	132.54	105.76	69.07
	Amount (Rs in lakh)	9.63	7.69	5.02
Centering and shuttering including ropping etc,	Qty in sqm @ Rs 354.44 per	519.68	391.50	282.24
	Amount (Rs in lakh)	1.84	1.39	1.00

उक्त से स्पष्ट था क कार्य की व शष्टियों की प्रमुख मदों की प्रस्ता वत मात्रा मे भन्नता थी, जो इस बात का द्योतक था क कार्य के आगणन के गठन मे स्थलीय सर्वेक्षण नहीं कया गया था। आगे देखा गया क निर्माण मे centering and shuttering के प्रस्ता वत कार्यो से कार्य की कुल लागत संबंधी अनुपात⁵ मे साम्य नहीं था, जिससे स्पष्ट था क गठित आगणन त्रुटिपूर्ण था। कार्य की लागत मे अनुपात 1:1.3:1 था जब क centering and shuttering के कुल प्रस्ता वत कार्य मे अनुपात 9 : 6 : 5 का था। इसी प्रकार आर सी सी कार्य मे कार्य की लागत अनुपात 1:1.3:1 के सापेक्ष 4:3:2 का अनुपात था, कार्य के डजाइन / ले आउट आगणन मे उपलब्ध न होने के कारण निर्माण संबंधी उक्त व शष्टियों की पुष्टि लेखा परीक्षा मे नहीं की जा सकी। स्पष्ट था क आर सी सी कार्य तथा centering and shuttering के अनुपात भन्न थे, जो त्रुटि पूर्ण आगणन का द्योतक था। मुखर्जी नगर मे जन मलन केंद्र के स्थलीय निरीक्षण मे पाया गया क कार्य स्थल नजुल भूम थी, निर्माण के संबंध मे डजाइन नहीं बनाई गयी थी, वद्युत एवं जल संयोजन के बिना ही दीवार पर प्लास्टर कार्य कराया जा

5

कार्य का नाम	Centering and shuttering	Cost of the work (Rs in lakh)
संत कबीर नगर पार्क मे जन मलन केंद्र	20.16+158.40+519.68+327.25= 1025.49	23.14
मुखर्जी नगर मे जन मलन केंद्र	13.44+105.60+391.50+207.11= 717.65	28.44
सोनिया होटल के सामने सामुदायिक भवन	13.44+105.60+282.24+119.68= 520.96	22.20

रहा था। शौचालय का निर्माण प्रस्तावत नहीं था। इन तथ्यों के इंगत कए जाने पर वहाँ पर उपस्थित ठेकेदार प्रतिनिध द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया क इस संबंध मे कार्यवाही की जाएगी। स्पष्ट था क बिना कसी नियोजन के कार्य सम्पन्न कराया जा रहा था। संबन्धित पत्रावलियों के अवलोकन मे कार्य मे प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जांच संबंधी प्रतिवेदन नहीं पाये गए।

जून 2017 मे ठेकेदार के साथ अनुबंध गठित कए जाने के 06 माह की अवध (निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा) के व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं कए जा सके थे।

इस प्रकार रु 73.78 लाख की लागत से प्रस्तावत 03 जन मलन केंद्र / सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण त्रुटिपूर्ण गठित आगणन के आधार पर कराया जा रहा था, कार्यों के ले आउट नहीं तैयार कए गए थे, जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके क कार्य स्थल पर क्या निर्माण कया जाना था। गुणवत्ता सुनिश्चित कए जाने हेतु कार्य मे प्रयुक्त निर्माण सामग्री की जांच नहीं कराई जा रही थी।

लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे इंगत कए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है, अ भयंत्रण वभाग मे योजना स्वीकृति नियुक्त अधशासी / सहायक अ भयंत्रा द्वारा दी जाती है, कार्य क व शस्तियों मे भन्नता के संबंध मे इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया तथा बताया गया क कार्य के शीघ्र पूर्ण कर लए जाने की संभावना है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्यों क निर्माण कार्यों मे व शस्तियों की प्रमुख मदों की प्रस्तावत मात्रा मे भन्नता थी, जो इस बात का द्योतक था क कार्य के आगणन के गठन मे स्थलीय सर्वेक्षण नहीं कया गया था, निर्माण मे centering and shuttering के प्रस्तावत कार्यों से कार्य की कुल लागत संबंधी अनुपात मे साम्य नहीं था जो त्रुटिपूर्ण आगणन गठित कए जाने की स्वतः पुष्टि करता है।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग II-‘ब’

प्रस्तर 7:- इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `1,42,786/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त वनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रयान्वयन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.- II दिनांक 13 अगस्त 2014 के अनुसार, व भन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त वनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियम कए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें व भन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्यु उपरान्त सहायता, च कत्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के ववाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल कट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित कये जाने हेतु प्रावधान निहित कये गये हैं । उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमकों की कल्याणकारी योजनाओं के लए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर के रूप में कल्याण बोर्ड की नि ध में जमा कए जाने का प्रावधान निहित है ।

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके कए जाने का प्रावधान है । इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में कए जाने की आवश्यकता है ।

नगर निगम, रुद्रपुर, जनपद - उधम सिंह नगर के चयनित निर्माण कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (मार्च, 2018) में पाया गया क इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान नहीं किया गया था | चयनित निर्माण कार्यों की जाँच में आगे पाया गया क इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार 17 निर्माण कार्यों के सापेक्ष `1,42,78,584/- की धनराश का भुगतान किया गया (सूची संलग्न) | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से 1% उपकर (लेबर सेस) के रूप में `1,42,786/- की धनराश की कटौती करके संबन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष कए गए भुगतानों में से उपकर (लेबर सेस) की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगत कए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया क शासनादेशों की जानकारी के अभाव में उक्त कार्यों पर 1% लेबर सेस नहीं काटा जा सका | इकाई ने आगे बताया क लेबर सेस की धनराश `1,42,786/- को संबन्धित ठेकेदारों से वसूलने के बाद राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांक 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त मुख्य नगर अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय 1% उपकर (लेबर सेस) की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर निगम रुद्रपुर द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एवं लेखापरीक्षा द्वारा चयनित निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सैस की कटौती न कए जाने का ववरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	बिल के भुगतान की धनराश	लेबर सैस की कटौती		
			जो की जानी थी @ 1%	जो की गयी थी	अंतर
01	वार्ड नं. 1 आजाद नगर मे राजकुमार के घर से हरदारी लाल और शेर सिंह के घर तक सीसी टाइल्स रोड व नाली का निर्माण कार्य	735958	7359.58	0	7359.58
02	वार्ड नं. 7 रमपुरा मे हरप्रसाद के घर से रूपम के घर तक नाले के ऊपर आरसीसी स्लेब व सीसी रोड का निर्माण कार्य	575685	5756.85	0	5756.85
03	इंद्रा कालोनी वार्ड नं 15 गली नं 2 मे संतोषी माता मंदिर के सामुदायिक भवन मे टाइल्स व रंगाई पुताई का कार्य	645367	6453.67	0	6453.67
04	वार्ड नं. 13 मे बलबीर सिंह के मकान से चमन लाल जगदीश कुमार के मकान (काशीपुर बाइपास रोड) तक साइड पटरी का निर्माण	557578	5575.78	0	5575.78
05	वार्ड नं. 13 मे हिन्द टायर सर्विस के सामने (नजदीक पु लस चौकी) डीडी चौक के पास साइड पटरी का निर्माण कार्य	766439	7664.39	0	7664.39
06	वार्ड नं. 18 रवीन्द्र नगर मे शीतला माता मंदिर के पास जन मलन केंद्र का निर्माण कार्य	610505	6105.05	0	6105.05
07	वार्ड नं. 16 मे हराधन दास के घर से शनि मंदिर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य	899354	8993.54	0	8993.54
08	वार्ड नं. 10 ए शयन फर्नीचर के सामने सीसी टाइल्स रोड का निर्माण कार्य	612928	6129.28	0	6129.28

क्रम संख्या	कार्य का नाम	बिल के भुगतान की धनराश	लेबर सेस की कटौती		
09	वार्ड नं. 20 गायत्री पार्क सीसी टाइल्स पटरी का निर्माण कार्य	720221	7202.21	0	7202.21
10	वार्ड नं. 1 आजाद नगर फेज 1 मे खड़क सिंह के घर से नरेश व मेवा राम के घर तक सीसी टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	526922	5269.22	0	5269.22
11	वार्ड नं. 15 इन्दिरा नगर कालोनी गली नाम. 5 मे गुरुद्वारा फर्श का निर्माण कार्य	1043843	10438.43	0	10438.43
12	वार्ड नं. 10 मे पोस्ट ऑफिस के पास सीसी टाइल्स रोड का निर्माण कार्य	1055250	10552.5	0	10552.5
13	वार्ड नं. 18 मे छठ घाट हेतु टीन शेड एवम साइड पटरी का निर्माण कार्य	1898255	18982.55	0	18982.55
14	वार्ड नं. 2 ठाकुर नगर मे रजीत वशवास के घर से कार्तिक वशवास के घर तक सीसी टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	569327	5693.27	0	5693.27
15	वार्ड नं. 17 मे मेवा राम के घर से अशोक के घर तक सीसी टाइल्स रोड व नाली का निर्माण कार्य	298672	2986.72	0	2986.72
16	अमृत योजना अंतर्गत वार्ड नं. 1 ट्रांसिट कैंप सी ब्लॉक के पार्क का सौंदर्यकरण	1781036	17810.36	0	17810.36
17	वार्ड नं.-09, ट्रेनिंग सेंटर होम साइन्स कॉलोनी मे सीसी टाइल्स रोड का निर्माण कार्य	981244	9812.44	0	9812.44
	योग	14278584	142785.84	0	142785.8

भाग 2(ब)

प्रस्तर 8:- धनराश रु 15.82 लाख के कराए की वसूली का लंबित रहना एवं दुकान कराए की दरों का पुनरीक्षण न कया जाना ।

दुकाने कसी भी निकाय की महत्वपूर्ण संपत्त होती हैं । जिनसे प्राप्त होने वाला कराया उस निकाय/निगम की आय का मुख्य स्रोत होता है । इस हेतु कराए की वसूली नियमत रूप से कया जाना अति आवश्यक होता है, ताक प्राप्त धनराश का उपयोग अन्य सम्पत्तियों के निर्माण एवं वकास कार्यों पर कया जा सके ।

नगर निगम रुद्रपुर की दुकानों से संबन्धित अभलेखों की नमूना लेखा परीक्षा (मार्च 2018) मे पाया गया क वर्ष 2016-17 के अंत तक व भन्न क्षेत्रों मे स्थित इकाई की दुकानों से निम्न ववरणानुसार कराया वसूली लंबित थी :- (धनराश रु मे)

क्र.सं.	क्षेत्र जहां दुकाने स्थित हैं	दुकानों की संख्या	वगत वर्षों की अवशेष धनराश	वर्ष 2016-17 की मांगे	कुल वसूली हेतु राश	वसूल की गयी धनराश	बकाया धनराश
1	प्रंस होटल	47	141161	435598	576759	297742	279017
2	काशीपुर रोड	60	212865	441026	653891	470780	183111
3	गल्ला मंडी	12	27900	142764	170664	122684	47980
4	काशीपुर बाईपास रोड	24	295435	217114	512549	116557	395992
5	सब्जी मंडी	98	125667	210446	336113	194096	142017
6	गुरु नानक स्कूल के सामने	17	75522	171768	247290	77344	169946
7	सरगोटिया	23	75522	169480	245002	127134	117868
8	काशीपुर रोड खोखे	34	29610	14484	44094	5540	38554
9	सब्जी मंडी फड	70	75703	77223	152926	16390	136536
10	सब्जी मंडी आढत	22	41788	60626	102414	28235	74179
	योग	407	1101173	1940529	3041702	1456502	1585200

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क इकाई की दुकानों के कराए से कुल वसूली योग्य धनरा श की 52% धनरा श अभी भी वसूली हेतु लंबित पड़ी हुई थी ।

इसके अतिरिक्त इकाई की कुल 407 दुकानों मे से अधिकांश की अनुबंध अव ध वर्ष 2006 तक समाप्त हो चुकी थी तब से लेखापरीक्षा ति थ (मार्च 2018) तक लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात भी इकाई द्वारा दुकान के कराए की दरों मे यथो चत वृद् ध के उद्देश्य से कोई पुनरीक्षण नहीं कया गया जो निगम की निजी आय स्रोतों की वृद् ध के प्रति पंगुता को परिल क्षत करता है ।

उपरोक्त तथ्यों को लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा गया क कार्मकों की कमी के कारण न्यून वसूली हो पायी एवं नोटिस जारी कर कराए की दरों मे पुनरीक्षण के प्रयास कए जा रहे हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क कराए की वसूली निय मत रूप से की जानी चाहिए एवं दुकानों की अनुबंध अव ध समाप्त होने के उपरांत यथाशीघ्र नए अनुबंध कर लेने चाहिए थे ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 9:- इकाई द्वारा शासनादेश के विरुद्ध रु. 733728/- के वाहन का क्रय किया जाना।

परिवहन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 65/IX-1/2013/2015/2011 दिनांक 07 जनवरी 2013 के अनुसार श्रेणी D अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगम के अधिकारी आदि/समकक्ष के लिए शासकीय वाहनों के मॉडल/मूल्य की अनुमान्यता 06 लाख तक ही है।

इकाई के द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु महिंद्रा बोलर (Bolero Power+ZL Micro Hybrid BS4) के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्रय किए गए वाहन का मूल्य रु. 733728/- (रु. 732307+रु. 1421) था जो कि शासनादेश का उल्लंघन था।

इस इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश की जानकारी के अभाव में क्रय कर लिया गया था। भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 10:- विभिन्न मदों के ठेकों से सम्बन्धित वसूली रु. 37.99 लाख का लंबित रहना।

किसी भी स्थानीय निकाय का आय में उसके निजी स्रोतों से होने वाली आय जैसे विज्ञापन के ठेके/तहबाजारी/पार्किंग एवं झील इत्यादि के ठेकों से प्राप्त होने वाली धनराशि का मुख्य योगदान होता है।

इकाई के उक्त ठेकों से संबन्धित अभिलेखों/पंजिका का जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा विभिन्न वर्षों में दिये गए ठेकों की धनराशि में से अभी भी निम्न विवरणानुसार धनराशि की वसूली अवशेष थी।

क्र.सं.	ठेके का नाम	ठेकेदार का ववरण	ठेके की कुल धनरा श	वसूली की गयी धनरा श	बकाया धनरा श
1	तह बाजारी	श्री सकीउल्ला खाँ पुत्र श्री हसी उल्ला खाँ	2727786	2727786	-
2	पार्किंग	श्री निरोद वरन अ धकारी पुत्र श्री दीन बंधु अ धकारी	3097927	3097927	-
3	स्लॉटर हाउस	श्री दुर्गेश गुप्ता पुत्र श्री ब्रह्मानन्द गुप्ता	833000	616500	316500 (आर.सी.जारी दिनांक जुलाई 2017)
4	रिक्शा लाईसेन्स आदि	श्री दुर्गेश गुप्ता पुत्र श्री ब्रह्मानन्द गुप्ता	835000	582500	252500
5	वज्ञापन	मै.मी डया 24*7	6860000	3530000	3330000
		योग	14353713	10554713	3799000

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क उक्त ठेकों से संबन्धित कुल रु. 37.99 लाख की धनरा श वसूली हेतु लंबित थी। आगे जांच में यह देखा गया क निगम के पास निजी स्रोतों से होने वाली आय को शा सत करने वाले स्पष्ट बाईलाज.बोर्ड प्रस्ताव उपलब्ध नहीं थे जो निगम के निजी स्रोतों से होने वाली आय के प्रति श थल रवैये को प्रद र्शत करता है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा क वसूली हेतु नोटिस जारी कए जा रहे हैं एवं उक्त संद र्भत स्पष्ट बाईलाजी.बोर्ड प्रस्ताव तैयार कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कए जायेगे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यो क न तो वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास कए ज रहे हैं और न ही इस संबंध में कोई स्पष्ट बाईलाज.बोर्ड प्रस्ताव बनाए गए हैं।

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुक्रम में संपत्त कर आरोपित किए जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172-73 में संपत्त कर लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 173 (1) में प्रावधान है कि धारा 172 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए संपत्त कर में निम्नलिखित कर सम्मिलित होंगे, जो आगे व्यवस्थित उपवादों, परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए नगर में भवनों या भूमियों पर लगाए जाएंगे-

(क) सामान्य कर, जो यदि ऐसा निर्धारित करे, अनुक्रमित मूल्य (graduated scale) से आरोपित किया जा सकता है,

(ख) जल कर जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहां निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो,

(ग) जल निस्सारण कर (drainage tax) जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहां निगम ने नालों (sewer) की प्रणाली की व्यवस्था की हो,

(घ) ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छता कर (conservancy tax) जहां निगम निस्सारण करने का कार्य करती है।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गयी नियमावली में स्पष्ट रूप से की अन्य व्यवस्था को छोड़कर ये कर यथास्थिति भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य (annual value) पर लगाए जाएंगे।

उक्त प्रावधान के अंतर्गत नगर निगम सीमांतर्गत आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों पर संपत्त कर स्विकार निर्धारण प्रक्रिया के तहत लगाया जाना निर्धारित किया गया था, संबंधित अभिलेखों की जांच में देखा गया कि:

- निगम द्वारा स्विकार निर्धारण प्रक्रिया के तहत फरवरी 2018 तक आवासीय भवनों के 15206 वतरित फार्मों के सापेक्ष 1942 से तथा व्यावसायिक / अनावासीय 2759 वतरित फार्मों के सापेक्ष 254 भवनों से कर की वसूली की गयी थी, जो कि कुल वतरित फार्मों के सापेक्ष मात्र 12 प्रतिशत था।
- इकाई द्वारा मांग तथा वसूली के संबंध में पंजी का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
- आवासीय तथा अनावासीय भवनों के संबंध में सर्वेक्षण कार्य गतिमान था।

इस प्रकार, निकाय संपत्त कर के रूप में प्राप्त होने वाले स्वयं के राजस्व के एक बड़े हिस्से से वंचित था, तथा वतरित किए गए फार्मों के सापेक्ष भी वसूली का प्रतिशत काफी कम था।

लेखापरीक्षा (मार्च 2018) में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि नयी प्रक्रिया लागू होने की वजह से वसूली कम हुयी है, भवनों के सर्वेक्षण कार्य किए जा रहे हैं तथा मांग एवं वसूली हेतु पंजी का रखरखाव किया जा रहा है।

तथ्य प्रकाश में लाया जा रहा है।

STAN

प्रस्तर 2:- नगर निगम द्वारा अमृत योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों के सम्पादन में नियमों का पालन न किया जाना।

नगर निगम द्वारा अमृत⁶ योजना अंतर्गत संपादित कराये गए निम्न कार्यों की जांच की गयी:

- वार्ड नंबर एक ट्रांज़िट कैंप सी- ब्लॉक में पार्क के सौंदर्यीकरण हेतु निवदा आमंत्रित कर (सितम्बर 2016) वभागीय दरों से 0.20 प्रतिशत कम पर कार्य आवंटित कर ठेकेदार के साथ अनुबंध गठित किया गया था (अक्टूबर 2016), अनुबंध के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा छः माह थी।
- वार्ड नंबर सात में एकराम आर्य पार्क के सौंदर्यीकरण हेतु ₹ 36.15 लाख का आवंटन प्राप्त था, जिसमें ₹ 28.46 लाख से निर्माण कार्य एवं ₹ 7.69 लाख से झूले इत्यादि लगाए जाने थे। कार्य के आवंटन हेतु निवदा आमंत्रित कर मेसर्स एम एम कन्स्ट्रक्शन को वभागीय दरों से 22.99 प्रतिशत कम पर कार्य का आवंटन किया गया था।

इकाई की लेखापरीक्षा (मार्च 2018) में देखा गया कि ट्रांज़िट कैंप सी- ब्लॉक कार्य में निर्धारित समय से 11 माह का अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, इस स्थिति में उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के GPW- 9 के बिन्दु संख्या 4.5 के अनुसार ठेकेदार से विलंब हेतु क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की गयी थी, जबकि विलंब के संबंध में ठेकेदार को मात्र 15 दिन का सीमा वस्तु दिया गया था। ठेकेदार के बिलों से रायल्टी, लेबर- सेस की कटौती भी नहीं की गयी थी। वार्ड नंबर सात में एकराम आर्य पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य में नियमानुसार कटौती नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्षा में इंगत किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि नियमानुसार कटौती की कार्यवाही की जाएगी।

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

⁶ अमृत योजना : Atal mission for Rejuvenation and Urban transformation yojna

प्रस्तर 3:- इकाई द्वारा उत्तराखंड अधप्राप्ति नियमावली का उलंघन करते हुए रु 2.59 लाख के उपकरणों का क्रय ।

उत्तराखंड अधप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) (संसोधन) नियमावली, 2015 के नियम 09 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर रु 50000/(पचास हजार) से अधिक तथा रु 3.00 लाख (रु तीन लाख) तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय वभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है ।

इकाई के द्वारा जून 2017 में जिला अधिकारी, उधम सिंहनगर द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में 10 सीसी टीवी कैमरे, 02 डी.वी.आर. व 02 एलईडी लाइटस स्क्रीन की खरीद व लगवाने का कार्य कराया गया। जिसके अभिलेखों का जांच में पाया गया कि सीसी टीवी कैमरे व एलईडी स्क्रीन लगवाने हेतु कोटेशन तीन फर्मों से प्राप्त कर क्रय किया गया था। मै. भारती सॉफ्ट, रुद्रपुर में जेमडी इण्टरप्राइजेज, हल्दवानी तथा मै सुपर टैक कम्प्यूटर सर्विस, हल्दवानी में से दो फर्मों (मै भारती सॉफ्ट तथा मै. जेमडी अण्टरप्राइजेज, हल्दवानी) के फोन नंबर (8958798733) समान थे, साथ ही तीनों कम्पनियों की कोटेशन के अनुसार भुगतान एक ही कंपनी मै. भारती सॉफ्ट, रुद्रपुर, के पत्र में किया जाना था। और अंत में मै भारती सॉफ्ट, रुद्रपुर की निवेदा को ही अंतिम मंजूरी भी प्रदान की गयी। इससे यह सद्ध होता है कि तीनों कोटेशन एक ही कंपनी द्वारा भरी गयी थी तथा क्रय समिति ने भी उनको ठीक से जांचे बिना स्वीकृत कर दिया जैसा कि कोटेशनों पर क्रय समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर न होना दर्शाता है। जिससे प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त किए बिना क्रय करने से अधप्राप्ति नियमावली के मौलिक सद्धान्त पारदर्शता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता का हनन हुआ।

इस प्रकार, उत्तराखण्ड अधप्राप्ति नियमावली, में प्रावधानित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना तथा क्रय के संबंध में आवश्यक व शष्टियों के निर्धारण के बिना रु. 2.59 लाख की सामग्री का क्रय किया गया।

इसे इंगत किये जाने पर इकाई ने कोई उत्तर नहीं दिया।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर, जनपद- उधम सिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) वाहन की मरम्मत सम्बन्धी पत्रावली

2. सतत अनियमितताएं:

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	अवध
01		
02		

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर, जनपद- उधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय